High Courts suggested that the Salary of High Court Judges may be exempted from income tax.

(e) The Government have at present no proposal under consideration to revise the salaries of judges of the Supreme Court and the High Courts or to exempt these salaries from income tax.

विश्रामपुर के आस-पास पाया गया कोयला

716. **श्री गुरुदेव गुप्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में विश्रामपुर के इर्द-गिर्द पाया जाने वाला कोयला उच्च किस्म का है जिसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिये किया जा सकता है और क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने भी इस क्षेत्र में उच्च श्रेणी का कोयला उपलब्ध होने की सूचना सरकार को दी थी; और

(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र में उपलब्ध होने वाले कोयले को मध्य प्रदेश के बिरसिंगपुर ताप विद्युत केन्द्र के लिये सुरक्षित रखने का विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) विश्रामपुर के आस-पास के क्षेत्रों में समन्वेषण करने से अच्छी किस्म और साथ ही घटिया किस्म का कोयला भी मिलने की संभावना हो गई है । ड्रिलिंग कार्य अभी भी चल रहा है । इस समय किसी भी ऐसे बिजलीघर के लिए कोयले की उपलब्धता के बारे में वचन देना समय-पूर्व होगा जिसके लिए आमतौर पर घटिया ग्रेड के कोयले का इस्तेमाल होता है ।

मध्य प्रदेश में जल-विद्युत परियोजनाओं का स्थापित किया जाना

717. **श्री गुरुदेव गुप्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जल-विद्युत परियोजनाएं स्थापित किये जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये गये परियोजना संबंधी प्रतिवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है और उनको कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि संसाधनों की कमी के कारण इन जल-विद्युत परियोजनाओं हेतु 1982-83 की वार्षिक योजना में कोई प्रावधान करना संभव नहीं है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्टों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है । परियोजना प्रस्तावों से संबंधित विभिन्न मामलों को अभी हल किया जाना है । अनिर्णीत मामलों के हल हो जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दी जा सकती है जिसके बाद निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान करने के लिए योजना आयोग इन प्रस्तावों की जांच करेगा ।

(ख) नई परियोजना जिनमें जल-विद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं हाथ में लेने के लिए मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना—1982-83 में एक मुश्त राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इनके लिए निवेश संबंधी अनुमोदन योजना आयोग द्वारा 1892-83 के दौरान जारी किए जाएंगे ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।